EDITORIAL

The 71st Foundation Day of NFPTE

The 71st Foundation Day of NFPTE (National Federation of Posts and Telegraph Employees) is being celebrated on 24 November 2024. NFPTE was established on November 24, 1954, as a unified and strong organization for the employees of the central Postal and Telegraph Department. Before this, during the freedom struggle, employees had small, fragmented organizations, but they lacked a powerful unified presence.

During the freedom movement, workers' organizations played an active role and awakened a strong consciousness for independence and democracy. After independence, the need for worker solidarity was strongly felt, leading to the formation of NFPTE. It consisted of nine different unions representing employees in posts, telegraphs, administrative offices, and other categories. Its purpose was to unite all unions under one umbrella to protect employees' rights and uphold national unity and integrity.

NFPTE took numerous steps for workers' welfare and succeeded in strengthening labor laws. However, in 1968, after a historic strike, the organization faced government repression, resulting in the imprisonment of many employees and the loss of NFPTE's recognition. Despite this, the organization's popularity remained high, and later, with the intervention of the then-President, C.V.V. Giri, NFPTE's recognition was reinstated.

Today, after 71 years since its inception, NFPTE remains a strong organization committed to raising the voice of central employees and safeguarding their rights.

In 1978, due to political intervention and policies, workers were once again divided when the then-Janata Party government, overnight, created a third federation for Postal and Telegraph employees and granted it recognition. Thus, after independence, three federations emerged in the Postal and Telegraph Department, disrupting the unity of workers due to political appeasement. Despite this, NFPTE continued to advance with the support of over 50% of employees in the department.

In 1986, the government divided the Postal and Telegraph Department, and as a result, NFPTE also split into two parts: NFPE for postal employees and NFTE for telegraph (telecom) employees. Initially, an umbrella organization was formed to keep these two federations united, but political conflicts led to NFPE and NFTE functioning separately.

NFTE became a leading federation in the telecommunications department, surpassing the other two organizations. In the 1990s, a reorganization of employee cadres in the telecommunications department began. Under the skilled leadership of Comrade O.P. Gupta, this restructuring created new positions and enabled financial advancements for telecom employees. Through his leadership, nearly 100,000 casual laborers were regularized after a prolonged struggle, including a nine-day hunger strike on a national scale. Today, many of those regularized workers have progressed to Group C, B, and even A positions.

In 1999, the government decided to corporatize two segments of the telecommunications department under a new telecom policy, namely the telecommunications operators and telecommunications

services. Comrade O.P. Gupta led a protest against this decision. Despite the opposition, the government was committed to corporatization and, on October 1, 2000, announced the transformation of these two sections into a corporation.

Under Comrade Gupta's leadership, NFTE, along with other unions, organized a historic three-day strike from September 6 to September 8, 2000. As a result, the government conceded, guaranteeing pensions, job security, and financial stability for the company.

During this period, all existing labor unions were ordered to re-register under the Industrial Workers' Union Act. In 2001, NFTE unified its six unions and re-registered under the name NFTE (BSNL). From then until 2004, NFTE continued to lead all BSNL employees. However, by 2004, other unions united under a single election symbol to compete against NFTE in membership verification elections, resulting in NFTE becoming an unrecognized union until March 2013. Despite this, NFTE narrowly lost multiple elections and maintained substantial employees support. In February 2013, management recognized the significant support for NFTE and adopted a policy of dual recognition for two unions. Thus, from April 2013, NFTE resumed its role as a recognized union, serving its members and actively supporting BSNL's strength.

It is a matter of pride that NFPTE, our parent organization, is celebrating its 71st Foundation Day on November 24, 2024. Therefore, all district branches, Business area branches, and circle branches are requested to celebrate this Foundation Day with great enthusiasm. Hoist the union flag, decorate union offices, organize collective meetings, and arrange refreshments. Take a pledge of loyalty to the unity and integrity of the nation and the Constitution. Commit to continually strive for BSNL employees' issues, such as wage revision, stagnation, promotional exams, a new financial upgradation policy, and other benefits. Stay prepared to engage in continuous struggles alongside other unions.

Long live NFTE –

Long live Employee Unity.

संपादकीय

मातृ संगठन एनएफपीटीई की 71वां स्थापना दिवस (24 नवंबर 2024)

ज्ञातव्य है कि मुल्क के आजादी के पूर्व और उस के चार साल बाद तक डाकतार विभाग या संपूर्ण केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई सशक्त श्रमिक संगठन की स्थापना नहीं की गई थी। आजादी के पूर्व भी डाक तार विभाग में छोटे–छोटे समूह के रूप में श्रमिक संगठन चलाए जा रहे थे। श्रमिकों पर स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बड़ी छाप थी और श्रमिक समुदाय की चेतना से स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला था। यह जग जाहिर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हो चुकी थी और श्रमिक समुदाय में भी पूर्ण स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की चेतना हिलोरे मारने लगी थी। श्रमिक समुदाय ने बढ़–चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बहुत से श्रमिकों ने अपनी आजीविका गवाई तथा बहुतों ने जेल की यातनाएं सही परंतु श्रमिक आंदोलन अग्रसर होता रहा।

शहीद लाला लाजपत राय की अगुवाई में सभी राजनीतिक विचारधारा सभी प्रकार के धार्मिक विचारधारा सामंती विचारधारा एवं पंथ निरपेक्ष विचारधारा के समस्त लोगों की गोलबंदी हो चुकी थी। श्रमिक संगठन आजादी की लड़ाई में हिरावलदस्ता के रूप में कार्य करने लगी थी। समय चक्र के साथ दुनिया के समस्त मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य अवधि के लिए आवाज उठाने लगे थे और श्रमिकों की चेतना धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद के प्रति प्रस्तुत होने लगी थी। हजारों लोगों की बलिदान एवं संघर्ष के ऊपर अंत 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली तथा 26 जनवरी 1950 को देश में जनतांत्रिक प्रणाली की स्थापना हुई। देश के संचालन एवं राजनीतिक नियंत्रण हेतु एक संविधान को अंगीकार किया गया। ठीक उसके चार वर्ष बाद 24 नवंबर 1954 को डाकतार विभाग में समस्त छोटे छोटे समूहों को गुलबंद करके राष्ट्रीय पैमाने पर समस्त डाकतार कर्मचारियों के लिए एक छतरी संगठन बनाने की तमन्ना कुछ नेताओं ने महसूस किया। तत्कालीन संघीय संचार मंत्री परम आदरणीय स्वर्गीय जगजीवन राम जी ने श्रमिक एकजुट में काफी योगदान दिया था। हेनरी बार्टन, दादा घोष, तारा पदो शरीक नेता इस कार्य के लिए अग्रसर हुए। स्वर्गीय कामरेड ओपी गुप्ता जी कामरेड दादा घोष के सानिध्य में आए और उनके नेतृत्व से अभिभूत होकर डाकतार कर्मचारियों के लिए एकीकृत संगठन के निर्माण में भी जी जान से जुट गए। जिसके प्रति फलस्वरूप 24 नवंबर 1954 को नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ एम्पलाइज की गठन संभव हो सकी। इस महासंघ के अंतर्गत 9 यूनियनों के गठन का प्रारूप तैयार किया गया जिसमें डाक विभाग आरएमएस टेलीग्राफ प्रशासनिक कार्यालय आदि के कर्मचारियों के लिए अलग–अलग 9 यूनियनों को मान्यता दी गई। जिसके नियंत्रि महासंघ के रूप में एनएफपीटीई से अनिवार्य रूप से संबंधता लेने की शर्त रखी गई। एनएफपीटीई के लिए भी इस एकीकृत महासंघ के रूप में यह शर्त रखी गई की वह 9 यूनियनों में से किसी को भी असंबद्ध नहीं करेगी तथा किसी दसवें यूनियन को भी किसी भी हाल में संबद्धता नहीं देगी।

इस प्रकार यह संगठन एक जुझारू संगठन के रूप में राष्ट्रीय पैमाने पर पूर्ण एकजुटता के साथ कार्य करने लगी तथा केवल डाक्टर विभाग ही नहीं अपितु संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारियों को मजबूत संगठन बनाकर अपनी हिफाजत करने तथा राष्ट्र की एकता अखंडता एवं लोकतंत्र की मजबूती के साथ बनाए रखने का संकल्प लेने के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में दिशानिर्देश दिया।

एनएफपीटीई सन् 1968 तक निर्बाध गति से चलती रही। इस बीच कर्मचारियों के हित में दर्जनों कल्याण नियमों का सृजन सरकार से कराने में सफल हुई। ऐसा कहना अतार्किक न हीं होगा कि यह संगठन तत्कालीन राजनीतिक सत्ता के लिए मुश्किलें पैदा करने लगी और सरकारें असहज होने लगी। इसी बीच 19 सितंबर 1968 को 1 दिन की पूर्ण हड़ताल की घोषणा हुई। यह ऐतिहासिक हड़ताल सरकार की जड़े दीला दी, जिससे क्षुब्ध होकर सरकार ने इस हड़ताल को कुचलने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। नेतृत्व के कई साथी गोलियों के शिकार हुए। लगभग 12000 कर्मचारी को जेल में बंद कर दिया गया। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय नेताओं को नौकरी से मुअतल एवं बर्खास्त कर दिया गया। एनएफपीटीई जैसे महान संगठन की भी मान्यता समाप्त कर दी गई। सरकारी प्रताड़ना यहीं समाप्त नहीं हुई। तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक विचारधारा के तहत एक नए संगठन को रातों–रात सृजित करते हुए उसे मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार श्रमिक संगठनों के एकीकरण के मात्र 14 साल बाद सरकारी षड्यंत्र के तहत कर्मचारियों की एकता का विभाजन कर दिया गया। फिर भी कई वर्षों तक गैर मान्यता प्राप्त स्थिति में रहने के बावजूद एनएफपीटीई के प्रति आम कर्मचारियों का अतिशय विश्वास के चलते यह संगठन गैर मान्यता प्राप्त स्थिति में भी बहुसंख्यक कर्मचारियों के समर्थन के साथ आगे बढ़ते रहा। बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री सी. वी.गिरी के हस्तक्षेप से एनएफपीटीई की मान्यता पुन बहाल की गई। यह संगठन कर्मचारियों के हिरावल दस्ता के रूप में कार्य करती रही।

राजनीतिक हस्तक्षेप एवं उसके नीतियों के अनुरूप श्रमिकों का विभाजन एक बार फिर 1978 में हुआ जब तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने रातों–रात डाकतार कर्मचारियों के लिए एक तीसरी महा संघ का सृजन करते हुए उसे मान्यता दे दी इस प्रकार आजादी के बाद राजनीतिक तुष्टीकरण हेतु श्रमिकों की एक एकजुटता को छिन्न–भिन्न करते हुए डाक तार विभाग में तीन महासंघ खड़ा कर दिए गए। बावजूद इसके एनएफपीटीई डाक तार विभाग में 50% से अधिक कर्मचारियों के समर्थन के साथ आगे बढ़ती रही। सन 1986 में सरकार ने डाक अवतार विभाग का विभाजन कर दिया इसके फलस्वरूप एनएफपीटीई ने भी अपने को दो भागों में विभाजित करते हुए डाक कर्मचारियों का नेतृत्व करने हेतु एनएफपीई एवं टेलीग्राफ्स (टेलीफोन) अर्थात टेलीकॉम कर्मचारियों के लिए एनएफटीई दो महासंघ अलग–अलग कार्य करने लगी। शुरू में इन दोनों महासंघों में एकजुट बनाए रखने के लिए एक नियंत्रित संगठन का गठन किया गया लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण वह चल नहीं पाया फलस्वरुप एनएफपीई एवं एनएफटीई अलग–अलग कार्य करने लगी।

एनएफटीई ने अन्य दो संगठनों को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी महासंघ के रूप में दूर संचार विभाग में अपनी पहचान जारी रखने में सफल रही। 90 के दशक में दूर संचार विभाग में कर्मचारियों के संवर्गों का पुनर्गठन करने की प्रणाली शुरू की गई। कामरेड ओ.पी.गुप्ता जी जैसे कुशल नेतृत्व ने उक्त पुनर्गठन का लाभ लेते हुए दूर संचार कर्मचारियों के लिए न केवल नए पदों का सृजन कराया अपितु उनके वित्तीय उन्नयन का भी मार्ग प्रशस्त किया। उनके नेतृत्व में लगभग एक लाख कैजुअल मजदूरों को नियमित घोषित किया गया। जिसके लिए एनएफटीई ने उनके नेतृत्व में बहुत संघर्ष किया। यहां तक की संपूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर नेतृत्व के लोगों ने नौ दिनों तक लगातार भूख हड़ताल की। फलस्वरुप 100000 कैजुअल मजदूरों को पक्की नौकरी मिलने में सफलता प्राप्त हुई। यह गौरव की बात है कि उन मजदूर समूह से वर्तमान में बहुत से लोग ग्रुप सी ही नहीं अपितु ग्रुप बी एवं ग्रुप ए के पदों तक पहुंच चुके हैं। वर्ष 1999 में सरकार ने नई टेलिकॉम पॉलिसी लागू करने के नाम पर दूरसंचार विभाग के दो खंड दूरसंचार परिचालक एवं दूरसंचार सेवाएं को निगमित करने का फैसला लिया। कामरेड ओ.पी.गुप्ता के नेतृत्व में इस फैसले का विरोध किया गया। परंतु सरकार निगम बनाने के लिए कटिबद्ध थी और केंद्र सरकार ने 01.10.2000 से दूरसंचार विभाग के दो अनुभागों को निगम में परिवर्तित करने की घोषणा कर दी।

कामरेड ओ.पी. गुप्ता जी के नेतृत्व में एनएफटीई ने अन्य संगठनों को साथ लेकर 6 सितंबर से 8 सितंबर 2000 तक तीन दिनों की अभूतपूर्व हड़ताल कराई। जिसके फलस्वरुप सरकार को झुकना पड़ा और कर्मचारियों के लिए सरकारी पेंशन की गारंटी उनके नौकरी की गारंटी एवं कंपनी को आर्थिक रूप से संपन्न रखने की गारंटी दी गई।

इस झंझावात के बीच ही पूर्व से संचालित सभी श्रमिक संगठनों को औद्योगिक श्रमिक संघ अधिनियम के मानदंडों के तहत अपने संविधान की रचना करने तथा उनका पुनः निबंधन कराने का आदेश जारी हुआ। एनएफटीई ने अपने सभी 6 यूनियनों को एकजुट कर सब को एकीकृत करते हुए 2001 में इसे पुनः पंजीकृत कराया। उसे पंजीयन के अनुसार इस महासंघ का नाम एनएफटीई (बीएसएनएल) हुआ। उसे समय से यह बीएसएनएल के समस्त कर्मचारियों का नेतृत्व 2004 तक किया इस बीच एनएफटीई बीएसएनल से पिछड़ते हुए तमाम संगठनों ने आपस में एकजुट होकर एक ही चुनाव चिन्ह पर एनएफटीई के खिलाफ सदस्यता सत्यापन निर्वाचन में खड़ी होकर एनएफटीई को प्राप्त किया। उसके उपरांत स्कूल बंदी के तहत लगातार मार्च 2013 तक गैर मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में कार्यरत रही। ऐसा देखा गया है कि लगातार 10 वर्षों तक मान्यता में नहीं रहने के बावजूद और समस्त संगठनों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर भी एनएफटीई बहुत ही कम मतों से पराजित होते रही। अंततः प्रबध यह महसूस किया कि एक अपार कर्मचारियों का समर्थन एनएफटीई के साथ है और इस सोच के तहत फरवरी 2013 में दोनों यूनियनों को मान्यता देने की नीति अपनाई गई। इस प्रकार एनएफपीटीई पुनः अप्रैल 2013 से मान्यता प्राप्त कर अपने सदस्यों की सेवा करने एवं बीएसएनल को सुदृढ़ रखने के लिए सभी संगठनों में अगले कतार में खड़े नजर आती है।

यह गौरव की बात है कि एनएफपीटीई हमारी मातृ संगठन है जिसकी 71वां स्थापना दिवस 24 नवंबर 2024 को होने जा रही है। अतः पूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर सभी जिला शाखा वाणिज्य क्षेत्र शाखा परिमंडलीय शाखा के साथियों को निवेदित किया जाता है कि स्थापना दिवस को अत्यंत धूमधाम से मनाएं। संगठन का झंडा लहराएं। यूनियन कार्यालय पर सजावट करें तथा सामूहिक बैठक एवं अल्पाहार की व्यवस्था करें। साथ ही यह संकल्प लें कि हम एनएफटीई के सदस्यगण देश की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय संविधान के प्रतिनिष्ठा रखते हैं। बीएसएनएल में कार्यरत सभी कर्मचारियों की समस्याओं यथा वेतन पुनरीक्षण, स्टैग्नेशन, पदोन्नति की परीक्षाएं, नई वित्तीय पदोन्नति नीति एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रयास जारी रखेंगे। अन्य संगठनों के साथ मिलकर अनवरत संघर्ष के लिए हर दम तैयार रहेंगे।

एनएफटीई जिंदाबाद

कर्मचारी एकता जिंदाबाद